अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति (सीटू)

पत्रिका

अक्टूबर 2008 केवल सदस्यों के लिए मूल्य 3 रूपए

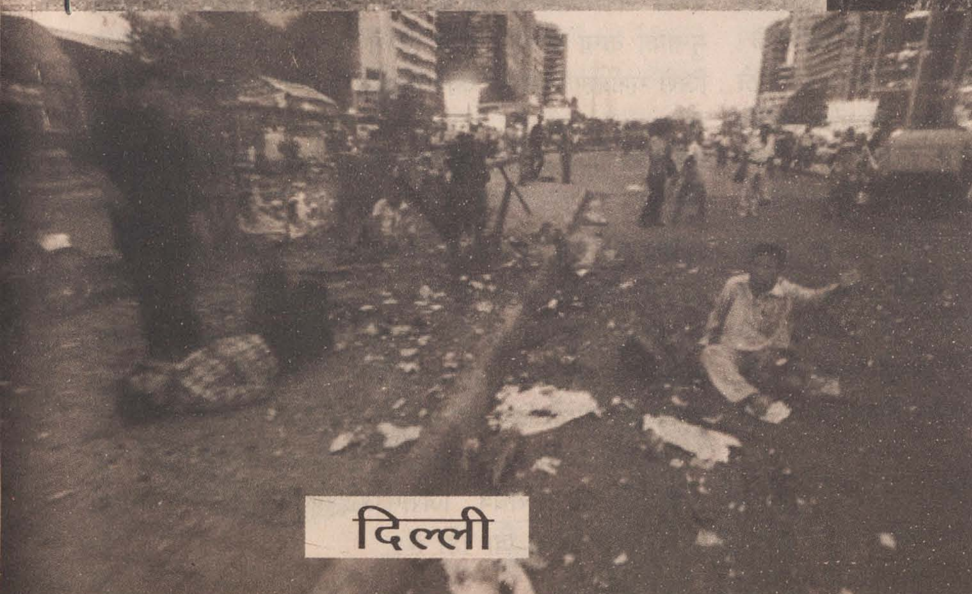

इनका मुंहतोड़ जवाब दो!

पैकेज्ड फूड पर मंत्रालय का संदिग्ध कदम

बहुत ही नामुनासिब तरीके से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक प्रस्ताव पेश किया कि आईसीडीएस के अन्तर्गत 3 से 6 वर्ष की आयु समूह के 8 करोड़ बच्चों को डिब्बाबंद/पैकेटबंद भोजन दिया जाए। इस प्रस्ताव को प्लान पैनल के तहत नकार दिया गया था, परन्तु रेणुका चौधरी के मंत्रालय द्वारा बार बार डिब्बाबंद/पैकेटबंद भोजन की गुहार लगाई जा रही है यद्यपि इस योजना का मुख्य उद्देश्य केवल डिब्बाबंद/पैकेटबंद भोजन तैयार करने वाली कंपनियों को बाजार उपलब्ध कराना ही है। इन कंपनियों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भी शामिल हैं,

विश्व के सर्वाधिक कुपोषित बच्चे भारत में हैं। देश में 3 साल से कम आयु के 80 प्रतिशत बच्चे और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली लगभग 60 प्रतिशत महिलाएं अनीमिया से ग्रस्त है; 46 प्रतिशत बच्चों का वजन अपनी आयु की तुलना में बहुत कम है; 38 प्रतिशत बच्चों का शारीरिक विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता; प्रति हज़ार बच्चों में 58 बच्चे अपना पहला जन्म दिवस मनाने से पहले ही इस दुनिया को विदा कह जाते हैं; इनमें 55 प्रतिशत बच्चों की मृत्यु कुपोषण के कारण होती है। उच्चतम न्यायालय ने भी भारत सरकार को आईसीडीएस को सर्वव्यापी बनाने का निर्देश दिया है ताकि 6 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को इस योजना के अन्तर्गत लाया जा सके। उच्चतम न्यायालय ने साफ साफ कहा है कि बच्चों को आमतौर पर ताज़ा पकाया हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

यह तो केवल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और रेणुका चौधरी ही है जो पूरक पोषण की पूर्ति पैकेज्ड फूड के रूप में करना चाहते हैं। उनका तर्क है कि आईसीडीएस के अन्तर्गत केवल पूरक पोषण की ही पूर्ति कराई जाती है और ताज़ा पकाए हुए स्थानीय भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व नही होते। ये दोनों ही तर्क बेबुनियाद हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, योजना आयोग एवं उच्चतम न्यायालय– ने भी साफ साफ कहा है कि गरीबी और कुपोषण से मुकाबला करने के लिए भोजन के पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में ताज़ा पकाया हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ''नैशनल इंस्टीच्यूट ऑफ न्यूट्रिशन'' ने रेखांकित किया कि मानव शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व फलों और ताज़ा सब्जियों द्वारा उपलब्ध होंगे। इसके अलावा डिब्बाबंद/पैकेटबंद भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया गया पाउडर बच्चों के लिए घातक सिद्ध होने की संभावनाएं हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा डिब्बाबंद/पैकेटबंद भोजन उपलब्ध कराने के लिए आवश्यकता और अतिरिक्त देखरेख की मांग करना कहां तक उचित है, और वो भी झूठे तर्क देकर कि सरकार आईसीडीएस को राशन प्रणाली द्वारा अनाज में छूट नही दे रही है। आखिर क्यों महिला एव बाल विकास मंत्रालय राज्य सरकारों से डिब्बाबंद/पैकेटबंद भोजन पर सर्वे की रिपोर्ट की मांग कर रहा है? बिल्कुल निरर्थक है जबकि आंगनवाड़ी कर्मचारियों सहित सभी इसका विरोध कर रहे हैं।
निःसंदेह यह कदम केवल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि डिब्बाबंद/पैकेटबंद भोजन और बेबी फूड/ बिस्कुट जैसी कंपनियों की नज़र इस देश के उस सबसे बड़े बाज़ार पर है जिसमें 6 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं।

इसमें कोई रहस्य नही है कि बड़े निगम भारत के कुपोषित बच्चों और गरीब जनता का इस्तेमाल करके बहुत ही अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। हाल ही में जीनीवा आधारित संगठन जिसे ग्लोबल एलाएंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन (GAIN) के नाम से जाना जाता है, ने भारत में 'इंफेन्ट एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन (IYCN) स्थापित करने का निर्णय लिया है।

GAIN एक ऐसा संगठन है जोकि 'छिपी भूख के लिए संघर्ष' के लिए ग्लोबल फूड जैन्ट ग्रुप डेनन , यूनिलिवर और कारगिल के साथ कार्य करता है। इसकी नीतियों के अनुसार यह पारम्परिक स्वास्थ्य अभियान को पंसद नही करता। यह पोषक आहार के लिए नए बाज़ार का निर्माण करता है। भारत में उनका कार्यक्रम है ''सार्वजनिक – नीजि भागीदारी'' के साथ ''कुपोषण से संघर्ष'', जिसमें आईसीडीएस जैसी योजनाओं को शामिल किया जा रहा है।

बड़े निगम हमारे कुपोषित बच्चों का इस्तेमाल कर लाभ कमा रहे है और इसी तरह ये निगम कृषि संकट का इस्तेमाल कर भारतीय शासक वर्ग की मदद से बहुत मुनाफा कमा रहे हैं, हमें ऐसी गतिविधियों से सावधान रहकर मुकाबला करना होगा।

वास्तविक मुद्दे

राष्ट्र के समक्ष आज ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर सरकार द्वारा तुरन्त गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है जैसे हमेशा की तरह बढ़ती महंगाई; देश के विभिन्न भागों में आई बाढ़ें जिनसे लाखों ही लोग बेघर होकर उजड़ गए; आतंकवाद के विरोध में सक्रिय कदमों की आवश्यकता; अल्पसंख्यकों में पुनः आत्मविश्वास पैदा करना एवं सांप्रदायिक अनुरूपता को मजबूत करना और ऐसे ही कई अन्य गम्भीर मुद्दे। संसद में इन गंभीर मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए और इन मुद्दों का सामना करने के लिए सक्रिय कार्यो का निर्णय लिया जाना चाहिए।

परन्तु यूपीए सरकार और कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ भी नही कर रही हैं, परन्तु ये तो अपने भारत–अमरीका परमाणु करार और अमरिका का छोटा भाई बनने में ही लगे हुए हैं। संसद में संदिग्ध कार्यवाहियों से यूपीए सरकार ने किसी तरह विश्वास मत तो हासिल कर लिया लेकिन सरकार को महसमस कर रही है कि अब जाने के दिन दूर नहीं। स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार संसद का मानसून सत्र बुलाने में नाकामयाब रही है।

देश में आतंकवादी हमले हो रहे हैं। जयपुर के बाद बंगलुरू, अहमदाबाद, और दिल्ली को फिर से निशाना बनाया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में बम विस्फोट हुए जिनमें लगभग 25 लोगों की मष्त्यु हो गई और बहुत से लोग घायल हुए। इससे पता चलता है कि यूपीए सरकार कुछ अपराधियों को पकड़ने की बजाय देश में आतंकवादी नैटवर्क को उखाड़ने में विफल रही है।

एक बार फिर से उड़ीसा में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी है। वीएचपी नेता स्वामी लक्ष्मणानंदा की भयानकता से हत्या की गई। उनकी हत्या करने माओवादी दावा करते हैं। उनके अनुसार उन्होंने हत्याएं इसलिए की क्योंकि बजरंग दल ने राज्य में इसाईयों पर अमानविक हमले किए गए।सैंकड़ों घर और प्रार्थना स्थल जला दिए गए जिसमें कई लोगों को जिंदा जलाया गया जिनमें महिलाए एवं बच्चे शामिल थे। हजारों लागों को घरों से भागकर जंगलों में शरण लेनी पड़ी। परन्तु बीजेपी और बीजेडी सरकार की मुख्यमंत्री की ओर से इसाईयों पर किए गए इस फासीवादी हमले की निंदा भी नही की गई। अब बजरंग दल के कार्यकर्ता कर्नाटक में इसाईयों पर हमले कर रहे हैं और उनके प्रार्थनाघरों को जला रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने की बजाए राज्य की भाजपा सरकार द्वारा आदेश दिए गए है कि यह जांच की जाए कि इन इसाई संस्थानों के फंड का स्त्रोत क्या है।

बजरंग दल पर गम्भीर आरोप हैं कि वे लोगों को, देश के विभिन्न भागों में अल्पसंख्यकों पर हमले करने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। परन्तु यूपीए सरकार इन हिंदुत्व आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में असफल रही है। सीबीआई इन नव फासीवादी संगठनों को बचाने के प्रयत्न कर रही है।

यूपीए सरकार और यूपीए सरकार द्वारा जन हिताकरी नीतियों का कोई विकल्प उपलब्ध ना करा पाने की अक्षमता के विरूद्ध जनता में असंतोष और विवाद बढ़ रहे हैं। और भाजपा इसी अवसर का लाभ उठाकर मूर्खतापूर्वक सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के प्रयत्न कर ही है। यह 'पोटा' वापस लाने की इसकी यह पुरानी चाल को पुनः दोहराने के चिन्ह हैं। आडवाणी प्रत्येक राज्य को गुजरात बनाने के बात कहते नजर आते हैं। भाजपा जनता को भटकाने का प्रयत्न कर रही है। यह जनता का ध्यान जनता के ज्वलंत मुद्दों से हटाकर गैर मुद्दों की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रही है, ताकि नव उदारवादी नीतियों के खिलाफ संघर्ष को कमजोर बना सके, जिसका भाजपा समर्थन करती है।

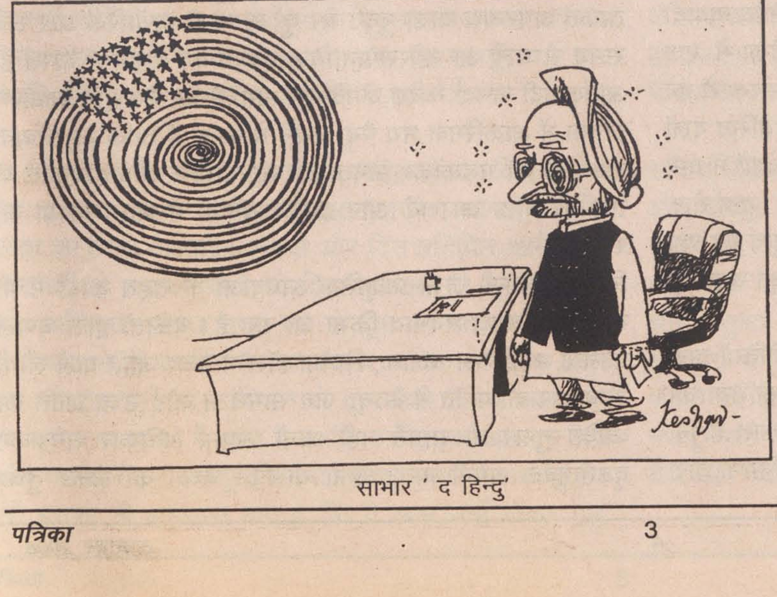

साभार ' द हिन्दु'

नव उदारवादी नीतियों के खिलाफ संघर्ष तब तक सफल नही हो सकता जब तक सांप्रदायिक ताकतों का हर ओर व हर तरह से खात्मा न कर दिया जाए। शासक वर्ग की फुट डालो और राज करो की इस नीति को लागू करने के प्रयत्नों से मजदूर वर्ग को सावधान रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है।

सीआईटीयू का भविष्य का कार्य
साम्राज्यवादी भूमंडलीयकरण के खिलाफ संघर्ष

देश में नव उदारवादी भूमंडलीयकरण के 17 सालों के दौर में इस वर्ष 20 अगस्त 2008 को मजदूर वर्ग की बारहवीं अखिल भारतीय आम हड़ताल एक साक्ष्य थी, असंख्य मजदूरों ने इस हड़ताल में भाग लिया जिसमें असंगठित क्षेत्र मजदूर और महिलाओं ने भारी संख्या में शामिल थे। किसानों, खेतिहर मजदूरों, ययुवाओं विद्यार्थियों और महिलाओं जैसे अनेको संगठनों की विभागों ने भी मजदूर वर्ग द्वारा उठाई जा रही मांगों का समर्थन किया।

वाम दलों ने यूपीए सरकार से अपना बाहरी समर्थन खींच लिया है, अब सरकार अपने अधूरे नव उदारवादी मुद्दों को लागू करके देश से बाहर बैठे अपने आकाओं को देश के भीतर ला रही है। वित्त मंत्री द्वारा यह पहले ही साफ किया जा चुका है। जिस आवश्यकता और रफ्तार से शासक वर्ग नव उदारवादी नीतियों को लाना चाहते थे, वे ऐसा करने में कामयाब नही हो पाए। परन्तु इस समय दौरान जनता और मजदूर वर्ग की कामकाजी और रहन सहन की स्थिति पर हमलों में काफी बढ़ोतरी हुई थी।

अपनी पुरानी पृष्ठभूमि को हासिल करने अर्थात् अपने अधिकारों और विपक्ष को हार का मुंह दिखाना आज मजदूर वर्ग के सामने एक चुनौती है। शासक वर्ग के हमले केवल संप्रांत रोजगार, मजदूरी और मजदूरों के कामकाजी स्थिति पर ही नही हुए हैं बल्कि इसके अर्न्तगत बहुत से अन्य हमले निहित हैं। शासक वर्ग और उनके द्वारा संचालित मीडिया द्वारा मजदूर वर्ग पर मानसिक रूप से हो रहे हमले बहुत ही गंभीर हमले है।

विकासशील देशों सहित पूरे विश्व का अनुभव बताता है कि साम्राज्यवादी भूमंडलीयकरण के अन्तर्गत गरीबी में बहुत बढ़ोतरी हुई है; अमीर और गरीब के फांसले की खाई चौड़ी हुई है; बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। फलस्वरूप पूरे विश्व में साम्राज्यवादी भूमंडलीयकरण का विरोध बढ़ रहा है। लातिनी अमरीका में, एक के बाद एक देश की जनता ने भूमंडलीयकरण वाली सरकारों को हराया है और जहां भी उन्हें अवसर मिला वाम और प्रोग्रेसिव दलों को चुना जा रहा है। वेनेज़ुएला और बोलिविया जैसे देशों में वाम सरकारें इन नीतियों को पलटने के प्रयत्न कर रही हैं। वहां तेल, भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर सरकार का प्रभुत्व बढ़ रहा है; गरीब जनता की कल्याण गतिविधियों पर सरकार का व्यय बढ़ भी रहा है।

अब तक घातक उदारीकरण और भूमंडलीकरण की नीतियों द्वारा गरीबी हटाने की बात की जा रही है। हमारे देश में मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा और स्वयं सेवी संस्थाओं का मत है कि साम्राज्यवादी भूमंडलीकरण का कोई विकल्प नही है। निगमों द्वारा संचालित मीडिया द्वारा ट्रेड यूनियनों और मजदूर वर्ग के संगठित अभियानों और संघर्षों को विकास विरोधी करार देकर दबाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा (जहां वामपंथ सरकारें सत्ता में हैं) के साथ– साथ अन्य कई राज्यों में भी 20 अगस्त की हड़ताल सफल रही परन्तु यह दिखाने के प्रयत्न किए गए कि हड़ताल का प्रभाव केवल इन्ही तीन राज्यों तक सीमित रहा। हड़ताल कोई मज़ाक नही है और मजदूर हड़ताल पर जाने के लिए तभी मजबूर होता है जब उसके दुःखों को दूर को दूर करने का कोई और चारा नही रह जाता। लेकिन हजारों लाखों मजदूरों की ज्वलंत समस्याओं को, जिनके कारणवश मजदूरों को हड़ताल पर जाने को बाध्य होना पड़ा, मीडिया द्वारा सामने नही लाया गया। बजाय इसके केवल यही रेखांकित करने के प्रयत्न किए गए कि हड़ताल के चलते मालिको का कितना नुक्सान हुआ और कुछ लोगों को कितनी परेशानी हुई। संगठित संघर्षों के विरूद्ध जनता को लामबंद करने और जनता को प्रभावित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। जबकि देश की बहुसंख्यक जनता मजदूर वर्ग द्वारा उठाई जा रही इन मांगों के पक्ष में है।

यह भी प्रयत्न किए जा रहे हैं कि मजदूर और परेशान जनता को धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पर बांट दिया जाए। इंफलेशन प्रति सप्ताह 12 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम आम जनता की पहुंच से बाहर हो रहे हैं, कृषि संकट के चलते किसान कर्जा न चुका पाने के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं, देश की लगभग 77 प्रतिशत जनता की दैनिक आय 20 रू से कम है और वे अपना जीवन यापन करने के लिए उसी में गुजारा करते हैं, देश इन हालातों में बजरंग दल, वीएचपी तथा अन्य आरएसएस बाशिंदे उड़ीसा, कर्नाटक और देश के अन्य भागों में गिरिजाघरों पर हमले करने में व्यस्त हैं; सांप्रदायिक और अलगाववादी ताकतें अमरनाथ यात्रा मुद्दे पर पूरे राज्य में पारंपरिक और लंबे समय से चली आ रही सांप्रदायिक एकता को तोड़ने में व्यस्त हैं, आतंकवादी जनता में देश के विभिन्न भागों में विस्फोट द्वारा साधारण जनता में आकस्मिक भय पैदा करने में व्यस्त है ताकि बहुसंख्यक सांप्रदाय को भड़काकर जनता को सांप्रदायिक सांप्रदायिकता के तौर पर बांटा जा सके और इसका चुनावों में लाभ उठाया जा सके।

बिहार में कोसी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के राहत कार्यों में भी दलितों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। दलितों द्वारा चप्पल पहनना, साईकिल चलाना, सिनेमा हॉल में उच्च जाति वाले लोगों के बराबर की पंक्ति में बैठना, जब सामने से कोई उच्च जाति का व्यक्ति गुजरे तो सामने नही आना, अपना अधिकार समझकर दृढ़तापूर्वक अपनी बात कहना या फिर बच्चों को लेकर तुच्छ

विवाद होना आम बात है। इन नियमों की अवहेलना उच्च जाति वालों द्वारा चुनौती समझी जाती है, और इतना कारण ही काफी है दलितों पर हमले करने के लिए। इन हमलों उनके घरों को जलाना उनकी महिलाओं का अपमान करना और हत्या करना भी शामिल है।
कर्नाटक उड़ीसा और देश के अन्य विभिन्न भागों में इसाईयों पर हमले, उनके गिरिजाघरों का जला देना जैसी कार्यवाहियों पर कांग्रेस नीत यूपीए सरकार द्वारा कोई कठोर कदम नही उठाए गए हैं। इसाईयों पर हमले करने के लिए कर्नाटक में भाजपा सरकार द्वारा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सज़ा भी नही दी गई बल्कि उलटे उन गिरिजाघरों के मिलने वाले फंड की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

इन बंटवारों को सबसे बड़ा शिकार है मजदूर वर्ग। मजदूर, प्रमुख रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों ने न केवल अपनी दैनिक आमदनी और जीवन खोया है बल्कि सांप्रदायिक झगड़ों की चपेट में आकर एक दूसरे से भिड़ने लगे हैं। इससे न केवल मजदूर वर्ग की एकता में फूट डाली गई है बल्कि इनका ध्यान भी स्वयं मजदूर विरोधी जन विरोधी नीतियों के खिलफ संघर्ष और वास्तविक मुद्दों से हट गया है। मजदूर वर्ग की एकता को तोड़ने के हमलों के प्रति मजदूर वर्ग को क्या प्रत्युत्तर मिल रहा है ? क्या हम कह सकते हैं कि मजदूर वर्ग इसका प्रत्युत्तर बहुत गम्भीरता से दे रहा है ?
जबकि भाजपा अपनी वही पुरानी कांग्रेस की ही तरह साम्राज्यवादी भूमंडलीयकरण की नीतियों पर अडिग है; कांग्रेस सांप्रदायिकता के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाने के लिए तैयार नही है; और न ही यूपीए सरकार इन आतंकवादी हमलों को रोक पा रही है। न तो कंग्रेस और ना ही भाजपा कोई जन हितकारी वैकल्पिक नीतियां ला रही है और द्विपक्षीय प्रणाली को बढ़ावा देने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। यह तो कुछ भी नही है जनता को वास्तविक विकल्प उपलब्ध कराने को नकारा जा रहा है और वही अमीरों के हितकारी नीतियों को लाया जा रहा है चाहे वह भाजपा हो या केंद्र में विराजमान कांग्रेस सरकार। क्या देश का मजदूर वर्ग इस सिथति और इसके प्रभावों के बारे में जागरूक है ?

क्षेत्र, विचारों, अंधविश्वासों अपभोक्तावाद, महिलाओं के प्रति पारंपरिक रवैया इत्यादी हथियार मीडिया में इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों और दिन प्रतिदिन आने वाली समस्याओं से हटाकर उन्हें संगठित आंदोलन से दूर रखा जा सके। अधिकतर जनता मुख्य रूप से युवा वर्ग आज इस बढ़ती हुई विचारधारा से प्रभावित हैं। फलस्वरूप, अधिक से अधिक आज स्वयं को ट्रेड यूनियन आंदोलन से दूर रखते हैं। वे ज्यादा से ज्यादा से लाभ कमाने में व्यस्त हैं जबकि उन्हें इसका अहसास नही है कि यह आंदोलन मजदूरों, कर्मचारियों के लाभों से संबंधित है। उन्हें इसका भी अहसास नही है कि ये लाभ उन्हें केवल एक मजबूत व्यापक संयुक्त संघर्ष से ही मिल सकते हैं। अधिक से अधिक महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, परन्तु उनके साथ भेदभाव भी बहुत किया जा रहा है। दहेज और महिलाओं पर हिंसा की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं।

नव उदारवादी भूमंडलीयकरण का विरोध तब तक मजबूत नही हो सकता जब तक मजदूर वर्ग पर हो रहे विचारधारात्मक हमलों का कड़ा विरोध न किया जाए। मजदूर वर्ग पर हर ओर से हमले कर रहा है और मजदूर वर्ग में इसके बारे में समझ बनाने और विचाराधारात्मक हमलों का विरोध करने में देश में ट्रेड यूनियन आंदोलन सफल हो रहा है।
यह एक तथ्यात्मक बात है कि प्रत्येक अखिल भारतीय आम हड़ताल में भाग लेने वाले मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। इन हड़तालों में मजदूरों के अलावा ट्रेड यूनियनों से संबंधितों की संख्या भी बढ़ रही है। वे न केवल हड़तालों में समर्थन देते हैं बल्कि राष्ट्र स्तरीय हड़तालों में शामिल भी होते हैं। इन हड़तालों में असंगठित क्षेत्र मजदूरों और महिला मजदूरों की भागीदारी रेखांकित करने योग्य है। और इसी समय, मजदूर वर्ग की संयुक्त एकता हड़ताली कदमों पर सक्रिय प्रभाव डालती है।

आज मजदूर वर्ग का मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र का बहुत ही मामूली सा हिस्सा ही संगठित हो पाया है। संगठित क्षेत्र में भी अधिकतर मजदूर जो निजी संगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं, को संगठित होने से रोका जाता है। आज मजदूर वर्ग का एक बहुत बड़ा भाग अवसरवादियों और ट्रेड यूनियन विरोधियों के प्रभाव में हैं। उनका नेतष्त्वमंडल या तो नव उदारवादी नीतियों का समर्थन करता है या यह मानता है कि इन नीतियों का कोई विकल्प नही है और इन नीतियों को बदला नही जा सकता। वे अपने सदस्यों को संयुक्त संघर्षों से दूर रखने का प्रयत्न करते हैं।

मजबूत संयुक्त आंदोलन, मजदूर वर्ग के संघर्षों और जन साधारण के अन्य वर्गों जिनमें ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं, से ही सक्रिय विरोध संभव हो सकता है। मजदूर वर्ग हर संभव विभागों को को संयुक्त संघर्षों में शामिल करने के प्रयत्न किए जाने चाहिए।

सकिय विरोध को आवश्यकता होती है मजबूत संयुक्त आंदोलनों और मजदूर वर्ग मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूर वर्ग के संघर्षों की। इस आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए मजदूर वर्ग के व्यापक विभागों को इसमें शामिल करने के प्रयत्न करने होंगे। और संयुक्त संघर्षों का विरोध करने वाले अवसरवादियों और यूनियनों के संघर्ष के विरोधियों के रवैयों के नकाब को उतार फेंकने की आवश्यकता है।
मजदूर वर्ग ने दिखा दिया है कि वे संघर्षों में भाग लेने के लिए तैयार हैं। प्रबंधन के गुंडों द्वारा हमले, पुलिस का दमन और बहुत

(शेष पृष्ठ 14 पर)

अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति (सीआइटीयू) की बैठक

अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति (सीआइटीयू) की बैठक 24–25 सितम्बर 2008 को चेन्नई में सम्पन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता तमिलनाडु राज्य कामकाजी महिला समन्वय समिति की संयोजिका मालती चित्तीबाबू ने की। सीआईटीयू अध्यक्ष एम के पंधे, महासचिव मोहम्मद अमीन और सचिव कनाई बैनर्जी ने इस बैठक में भाग लिया।

बैठक आरम्भ करने से पूर्व कम्यूनिस्ट आंदोलन के संस्थापक नेता हरकिशन सुरजीत, ट्रेड यूनियन आंदोलन एवं वामपंथ के नेता पी रामचंद्रन, सीटू तमलिनाडु राज्य कमेटी के फॉर्मर अध्यक्ष हेमचंद्रन, रेलवे मजदूर आंदोलन के संस्थापक नेता एस के धर को श्रद्धांजली दी गई।

25 सितम्बर की सुबह अचानक सीआइटीयू के वरिष्ठ नेता एवं कोषाध्यक्ष रणजीत बसु के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। कनाई बैनर्जी ने सीआईटीयू एवं ट्रेड यूनियन आंदोलन में रंजीत बसु की भूमिका का बखान किया और श्रद्धांजली अर्पित की गई।

अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति (सीआइटीयू) की संयोजिका के हेमलता ने विशाखापत्नम कन्वेंशन के बाद की गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की और आगामी कार्यो का प्रस्ताव भी रखा।

बैठक में भाग लेने वाले 17 राज्यों ने बहस में भाग लिया। उन्होंने अपने राज्यों, क्षेत्रों की गतिविधियों का वर्णन किया और उनसे प्राप्त अपने अनुभावों के बारे में भी बताया।

बहस में एम के पंधे ने प्रशंसा की कि अधिक से अधिक महिलाएं सीआइटीयू की गतिविधियों में भाग ले रही हैं। परन्तु उन्होंने रेखांकित भी किया कि सीआईटीयू की बहुत सी राज्य कमेटियों, मुख्य रूप से हिन्दी भाषी राज्यों में अभी तक राज्य स्तरीय समन्वय समितियों का गठन करना शेष है। उन्होंने कहा कि उन राज्यों में राज्य स्तरीय समन्वय समितियां गठित करने सभी संबंधित यूनियनों में बड़ी संख्या में महिलाओं को शामिल कर उप समितियां बनाना सुनिश्चित करने का प्रयत्न करेगा। उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं का विकास करने और उन्हें यूनियनों और सीआईटीयू में नेतृत्व पद तक लाकर उत्तरदायित्व सौंपने के लिए ट्रेड यूनियन कक्षाएं आयोजित करने पर जोर दिया।

सीटू सचिव कनाई बैनर्जी ने ट्रेड यूनियन आंदोलन में महिला मजदूरों की भूमिका के बारे में ट्रेड यूनियनों में, जागरूकता फैलाने में अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति की भूमिका के बारे में दुख जताया। उन्होंने जोर दिया कि आंदोलन के विस्तार के साथ और अधिक साथियों की आवश्यकता होगी इसलिए कामकाजी महिला कार्यकर्ताओं का विकास किया जाए।

बैठक में सभी राज्य कामकाजी महिला समन्वय समितियों को आहवान किया गया कि वे 'आशा' कार्यकर्ताओं, मिड डे मील मजदूरों को संगठित करने और यूपीए सरकार के विश्व बैंक के निर्देशों पर आईसीडीएस का पुर्नगठन करने कदमों का विरोध में संयुक्त अभियानों में सीआईटीयू राज्य कमेटिय़ों के प्रयत्नों में सहयोग दें। सभी सदस्यों ने इस बात पर सहमति जताई कि 'द वॉयस ऑफ द वर्किंग वुमन' का सर्कुलेशन बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं और वे इसके लिए योजना बनाऐंगें।

बैठक ने तमिलनाडु की सीआटीयू राज्य कमेटी एव कामकाजी महिला समन्वय समिति का धन्यवाद अदा किया कि उन्होंने बैठक के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की।

कामरेड रणजीत बसु

सीआइटीयू के कोषाध्यक्ष कामरेड रणजीत बसु का 25 सितम्बर, 2008 को नयी दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से देहान्त हो गया। वह 64 वर्ष के थे। वह अपने जीवन के आरम्भिक काल में ही ट्रेड यूनियन गतिविधियों में भाग लेने लगे थे। वह उस समय गलैक्सो फार्मास्यूटिकल्स में काम किया करते थे। वह गलैक्सो में काम करते समय ही मेडिकल रिपर्जेटेटिव्स यूनियन के एक सक्रिय पदाधिकारी थे। ट्रेड यूनियन गतिविधियों में बेहद सक्रिय होने के फलस्वरूप वह बिहार स्टेट सेल्स रिपर्जेटेटिव्स यूनियन (बीएसएसआरयू) के अग्रणी संगठनकर्ता बन गए और बाद में उसके पदाधिकारी भी बने। ट्रेड यूनियन गतिविधियों के कारण गलैक्सो के प्रबंधन ने उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया। नौकरी से बर्खास्त हो जाने के बाद भी वह ट्रेड यूनियन गतिविधियों में बराबर सक्रिय रहे और पूर्ण कालिक कार्यकर्ता बन कर मेडिकल रिपर्जेटेटिव्स के मोर्चे पर काम करने लगे। इसी बीच वह फैडरेशन ऑफ मेडिकल एण्ड सेल्स रिपर्जेटेटिव्स (एफएमआरएआई) की अग्रिम पंक्ति के नेता बन गए थे। रणजीत बसु 1983 में दिल्ली आ गए और सीआइटीयू केन्द्र में पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगे। वह आगे चल कर सीआइटीयू के कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए और अपने जीवन के अंतिम सांस तक इसी पद पर काम करते रहे। कामरेड बसु के देहान्त का समाचार मिलते ही उनके सहयोगी भारी संख्या में सीआइटीयू के केन्द्रीय कार्यालय बी टी रणदिवे भवन नयी दिल्ली में पहुंच गए जहां उनकी देह को लाल झण्डे में रखा गया था। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव कामरेड प्रकाश कारात, सीआइटीयू के अध्यक्ष कामरेड एम के पन्धे, महासचिव मोहम्मद अमीन, किसान सभा के अध्यक्ष एस रामचन्द्रन पिल्ले, महासचिव के वरद राजन, संयुक्त सचिव नूरुल हुदा, खेत मजदूर यूनियन के सचिव सुनीत चोपड़ा, पार्टी पोलित ब्यूरो सदस्यों कामरेड सीताराम यैचुरी तथा बृंदा कारात, एटक के सचिवों, एसएफआइ के अध्यक्ष, सीपीआइ (एम) की दिल्ली राज्य समिति के सचिव पुष्पेन्द्र गरेवाल, लोक सभा में सीपीआइ (एम) गुट के नेता कामरेड बासुदेव आचार्य और लोक सभा के अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी इत्यादि नेता उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। इसके अलावा सीआइटीयू के केन्द्रीय सचिव मण्डल के सदस्य तथा कार्यकर्ता इस अवसर पर मौजूद थे।

१० जुलाई - आईसीडीएस बचाओ दिवस

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन ने 10 जुलाई 2008 को पूरे देश में आईसीडीएस बचाओ दिवस के रूप में मनाया। इस दिन विभिन्न राज्यों में जिला एवं परियोजना स्तर पर प्रदर्शन, रैलियां, धरने और जुलूस इत्यादी निकाले गए।

भारत सरकार ने विश्व बैंक के आदेशों पर आईसीडीएस को पुर्नगठन करने का निर्णय लिया। जिसे 'आईसीडीएस रिफॉर्मस् प्रोजैक्ट 4' के नाम से पुकारा जा रहा है। विश्व बैंक के आदेश पर इस 'आईसीडीएस संशोधित परियोजना 4' को प्राथमिक तौर पर आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, मंहाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश – 8 राज्यों में आरम्भ किया जाएगा। इसके अन्तर्गत लाए गए बदलावों को देशभर में लागू किया जाएगा। इस पुर्नगठन की प्रक्रिया से आईसीडीएस के अस्तित्व को ही समाप्त करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं, जबकि आईसीडीएस द्वारा देश के छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं को पूरक पोषण, स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

पश्चिम बंगाल में, आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने राज्यभर की परियोजनाओं में जुलूस निकाले और सीडीपीओ दफ्तर तक मार्च किया। वहां बैठकें की गईं जिसमें यूनियन और सीआइटीयू के नेताओं के अलावा किसान सभा, अखिल भातीय खेत मजदूर यूनियन, डीवाइएफआई, एसएफआई और अन्य जनसंगठनों के प्रतिनिधियों ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगों के प्रति समर्थन जताया। इस संघर्ष में लगभग 8,000 आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भाग लिया।

केरल में, राज्यभर की 114 परियोजनाओं में प्रदर्शन और धरने आयोजित किए गए। कासरगोड एवं कन्नूर, दो जिलों में जिला स्तरीय धरने व प्रदर्शन किए गए। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार राज्यभर से इन कार्यक्रमों में 38,505 आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भाग लिया।

आंध्र प्रदेश में राज्यभर की लगभग सभी परियोजनाओं में धरने और प्रदर्शन हुए जिसमें हजारों आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ में, आंगनवाड़ी एकता यूनियन (सीआइटीयू) ने 10 जुलाई को प्ररियोजना स्तरीय प्रदर्शन आयोजित किए जिसमें सैंकड़ों आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भाग लिया।

छत्तीसगढ़ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स एसोसिएशन जोकि आइफा से संबद्धित है, ने 11 जुलाई को रायपुर में राज्य स्तरीय रैली आयोजित की जिसमें राज्यभर से हजारों आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भाग लिया। राज्य सरकार द्वारा मानदेय बढ़ाने, गर्मियों की छुट्टियां इत्यादी जैसी राज्य स्तरीय मांगें भी उठाई गईं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य के बजट से आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का मानदेय क्रमशः 300रू और 150 रू बढ़ाने की घोषणा की।

जम्मू एवं कश्मीर में, राज्य की राजनैतिक कठिन परिस्थितियों के बावजूद कश्मीर की घाटी में तीन जिलों में जिला स्तरीय प्रदर्शन किए गए जिसमें प्रत्येक जिले से सैंकड़ों आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भाग लिया।

आंगनवाड़ी एकता यूनियन **मध्य प्रदेश**, ने 10 से 25 जुलाई 2008 तक आईसीडीएस के पुर्नगठन के विरोध में एक व्यापक अभियान चलाने का निर्णय लिया। **तमिलनाडु** में, परियोजना व जिला स्तरीय प्रदर्शन किए गए।

पंजाब में 8 जुलाई को आंगनवाड़ी मुलाजमों ने निदेशक के कार्यालय के आगे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने के लिए जुलूस के रूप में पहुंचकर ने अपनी मांगों के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद जब वे शांतिपूर्ण ढंग से निदेशक को अपनी मांगों पर आधारित ज्ञापन भेंट करने के लिए जाने लगीं तो पुलिस ने बिना किसी सूचना के 300 आंगनवाड़ी कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया जिनमें उषा रानी व सुभाष रानी भी शामिल थीं। पुलिस स्टेशन में धरना देना शुरू करने और नारे लगाने पर पुलिस ने उन्हें पीटना आरम्भ कर दिया। प्रदर्शन का नेतृत्व यूनियन की अध्यक्ष उषा रानी ने किया। इस अवसर पर आयोजित सभा को उषा रानी तथा यूनियन की महासचिव हरजीत कौर ने सम्बोधित किया। उनका कहना था कि सम्बन्धित विभाग के मंत्री स्वर्णा राम और मुख्य मंत्री प्रकाश सिंह बादल से बार–बार आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगों पर बातचीत हो चुकी है पर उनके द्वारा आश्वासन दिए जाने पर भी अभी तक मांगों को पूरा नहीं किया गया। सीआइटीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कामरेड रघुनाथ सिंह ने इस अवसर पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों को अपनी मांगों के लिए लगातार संघर्ष चलाने का आह्वान किया।

बहुत सी राज्य कमेटियों ने इस अभियान को 20 अगस्त की मजदूर वर्ग द्वारा सरकार की कीमत वृद्धि व अन्य जन विरोधी नीतियों के विरोध में 20 अगस्त 2008 को आयोजित की जाने वाली अखिल भारतीय आम हड़ताल के अभियान को सफल बनाने के लिए जोड़ा। बहुत से राज्यों में 'देश का विकास बच्चों के बिना' नामक पुस्तिका का अंग्रेजी से स्थानीय भाषाओं में अनुवाद कर हजारों प्रतियां प्रकाशित की गईं।

पंजाबः सैंकडों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संघर्ष

काले चोले डालकर मार्च

पिछले कई दिनें से अपनी मांगों के लिए चण्डीगढ़ में निदेशक सामाजिक सुरक्षा महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय के आगे धरना दिए जाने पर भी सरकार की ओर से बात न किए जाने के कारण भड़की सैंकड़ो आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने 21 जुलाई, 2008 को काले चोले डाल कर मुख्य मंत्री के निवास स्थान की ओर मार्च किया। मार्च का नेतष्त्व पंजाब आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन की अध्यक्ष उषा रानी तथा महासचिव हरजीत कौर के अलावा सीआइटीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कामरेड रघुनाथ सिंह इत्यादि नेताओं ने किया। इन आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सेक्टर 16 के क्रिकेट स्टेडियम चौक के समीप स्थानीय पुलिस ने नाका लगा कर रोक लिया जिसके कारण उनके तथा पुलिस के बीच हाथा पाई की नौबत आ गई। चण्डीगढ़ पुलिस ने मुस्तैदी से काम लेते हुए मुख्य मंत्री के ओएसडी एन एस सांगा को बुला लिया। सांगा ने स्थिति में हस्तक्षेप करते हुए मुख्य मंत्री के साथ उनकी 30 जुलाई को बातचीत निश्चित कर दी। जिस पर आंगनवाड़ी मुलाजिमों ने शांत होकर मार्च समाप्त कर दिया।

मशाल जुलूस

आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन, पंजाब की ओर से चण्डीगढ़ में 16 अगस्त, 2008 को अपनी न्यायोचित मांगों की प्राप्ति के लिए मशाल जुलूस निकाला गया जिसका नेतष्त्व यूनियन की अध्यक्ष उशा रानी तथा महासचिव हरजीत कौर ने किया। यह जुलूस मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल के निवास स्थान की ओर गया। इस रोष मार्च को दूसरे नेताओं के अलावा सीआइटीयू की पंजाब राज्य समिति के महासचिव कामरेड रघुनाथ सिंह, आंगनवाड़ी नेत्री सुभाष रानी ने भी सम्बोधित किया। वक्ताओं का कहना था कि पंजाब सरकार की ओर से बार–बार आश्वासन दिए जाने पर भी आंगनवाड़ी मुलाजमों की मांगें मानी नहीं गई हैं। उन्होंने मांग की कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के घेरे में लाया जाए; उनके मानदेय को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए और भिन्न–भिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत मिलने वाले सामाजिक सुरक्षा के लाभ दिए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगें नहीं मानी गई तो इसके खिलाफ पहले से चल रहे संघर्ष को और तेज कर दिया जाएगा।

आंगनवाड़ी कर्मचारियों पर पुलिस का बर्बर लाठीचार्ज

पंजाब में पिछले लगभग तीन महीनों से अपनी उचित मांगों के लिए विधान सभा की ओर मार्च कर रहीं हजारों आंगनवाड़ी कर्मचारियों पर 8 सितम्बर, 2008 को पुलिस द्वारा भीषण लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसके कारण दर्जनों कर्मचारी घायल हो गए। पुरुष कर्मचारियों ने आंगनवाड़ी महिलाओं को बालों से पकड़ कर सड़क पर घसीटा जिसके कारण उनके कपड़े फट गए। लगभग 500 कर्मचारियों को पुलिस पकड़ कर थाना ले गई जबकि पंजाब आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन की अध्यक्ष उषा रानी और महासचिव हरजीत कौर पर झूंठे मुकद्दमें बनाए गए।

याद रहे, चण्डीगढ़ में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की ओर से पंजाब सरकार के समाज कल्याण निदेशालय के आगे धरना दिया जा रहा है। सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके खिलाफ राज्य के कोने–कोने से आई हजारों कर्मचारियों ने विधान सभा की ओर मार्च किया। लेकिन उनका जुलूस जैसे ही सेक्टर 17 पहुंचा, वहां बड़ी संख्या में तैनात पुलिस वालों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस पर उन्होंने वहीं अवरोधकों के पास बैठ कर धरना देने का फैसला किया।

इसी बीच अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन की ओर से कर्मचारियों पर पुलिस के बर्बर दमन की तीखी निंदा की गई है। उसने मांग की है कि राज्य सरकार तत्काल आंदोलनकारियों के साथ बातचीत करके उनकी

मांगों को पूरा करे। फेडरेशन ने इस सम्बन्ध में सभी राज्य इकाईयों को आंगनवाड़ी कर्मचारियों से मुख्यमंत्री को तारें भेजने का आह्वान भी किया है। सीआइटीयू की पंजाब राज्य समिति के अध्यक्ष विजय मिश्र तथा महासचिव रघुनाथ सिंह ने भी आंगनवाड़ी कर्मचारियों पर पुलिस के बर्बर दमन की तीखी निंदा की है।

बादल सरकार के पुतले जलाए गए

आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन, पंजाब की ओर से 17 सितम्बर को पूरे राज्य में आंगनवाड़ी कर्मचारियों पर पुलिस अत्याचारों के खिलाफ बादल सरकार के पुतले जलाए गए। प्राप्त समाचारों के अनुसार लुधियाना, जालन्धर, संगरूर, राजपुरा, पटियाला, खन्ना, रायकोट, जगरांव, होशियारपुर, गढ़शंकर, रोपड़, नवां शहर, बटाला, पठानकोट, अमृतसर, तरन तारन, भटिण्डा, मलोट, डेराबस्सी आदि स्थानों पर प्रदर्शन किए गए और धरने दिए गए। धरनाकारियों को यूनियन की अध्यक्ष उषा रानी, महासचिव हरजीत कौर, सुभाष रानी इत्यादि नेताओं ने सम्बोधित किया।

पश्चिम बंगाल आईसीडीएस यूनियन कन्वेंशन

पश्चिम बंगाल राज्य आईसीडीएस कर्मी समिति द्वारा 9 अगस्त 2008 को श्रमिक भवन, कोलकाता में 20 अगस्त 2008 की अखिल भारतीय आम हड़ताल के समर्थन में एक विशाल कन्वेंशन आयोजित की गई। संगठन की महासचिव रत्ना दत्ता द्वारा अखिल भारतीय आम हड़ताल के आधार पर, विश्व बैंक के निर्देशों पर आईसीडीएस का पुर्नगठन करने के सरकार के निर्णयों का विरोध करते हुए एक छः सूत्रीय मांगों सहित एक घोषणापत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने पुर्नगठन के नाम पर सरकार के प्रस्ताव के घातक परिणामों के बारे में विस्तार से बताया और चेताया कि यह कार्यवाहियां आईसीडीएस को समाप्त करने के लिए की जा रही हैं। कन्वेंशन में दक्षिणी बंगाल के 13 जिलों से लगभग 500 आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने भाग लिया और घोषणापत्र को एकमत होकर स्वीकारा।

अखिल भारतीय किसान सभा के नेता बिनॉय कोनार कन्वेंशन के मुख्य वक्ता थे। उन्होंने यूपीए सरकार की न्यूनतम सांझा कार्यक्रम का पालन न करने, जिस कारण वामपंथ ने अपना समर्थन वापस खींच लिया, पर यूपीए सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मनमोहन सरकार बढ़ती इंफलेशन और आसमान छूती महंगाई की आंधी में आम जनता की समस्याओं को पूरी तरह दरकिनार करके बुश प्रशासन से भारत अमरिका परमाणु समझौते को अंतिम रूप देने के वायदे को पूरा करने के लिए उत्सुक है। बिनॉय कोनार ने भारत अमरीका परमाणु समझौते के हमारे देश के आर्थिक, राजनैतिक और विदेश नीति से संबंधित मुद्दों के बारे में विस्तार से बताया।

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन की अध्यक्षा नीलिमा मैत्रा ने विश्व बैंक की आर्थिक सहायता द्वारा आईसीडीएस 'संशोधन' परियोजना 4 के निर्देशों को लागू किए जाने के बारे में बोलीं। उन्होंने कहा कि यह कार्यवाहियां देशभर में आईसीडीएस का पुर्नगठन करने की प्राथमिक प्रकियाएं हैं। उन्होंने प्रश्न किया कि हमारे समाज का भविष्य हमारे बच्च्चों को संतुलित भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा उपलब्ध कराए बिना हमारे देश का विकास कैसे हो सकता है?

कन्वेंशन में फैसला लिया गया कि सभी जिलों में इसी प्रकार की कन्वेंशनें की जाएं, और हड़ताल के लिए व्यापक अभियान चलाया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि राज्य के सभी आंगनवाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं हड़ताल में भाग लें।

झारखंड

झारखंड के संतल परगना क्षेत्र के लगभग 500 आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने 23 जून 2008 को दुमका में भूख हड़ताल में भाग लिया। भूख हड़ताल का उदघाटन आइफा अध्यक्ष नीलिमा मैत्रा ने किया। उन्होंने विस्तार से बताया कि सरकार द्वारा सुधार के नाम पर आईसीडीएस में लाए जा रहे बदलावों से तो आईसीडीएस का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा और आंगनवाड़ी कर्मचारियों पर इसके क्या प्रभाव पडेंगे। जनसमूह को सीआइटीयू व अन्य जनसंगठनों के नेताओं ने भी संबोधित किया। सीआईअीयू से संबद्धित झारखंड आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका यूनियन, जिसने भूख हड़ताल आयोजित की, ने राज्य सरकार से मांग की कि उनका मानदेय तुरन्त बढाया जाए, और राज्य में सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ मुहैया कराए जाएं। इस अवसर पर 'देश का विकास बच्चों के बिना' नामक सैंकड़ों पुस्तिकाओं की बिक्री की गई।

आईसीडीएस को गैर सरकारी संगठनों के सुपुर्द करना

आंध्र प्रदेश में अदीलाबाद जिले में उत्नूर और असीफाबाद आंईसीडीएस परियोजनाओं के अन्तर्गत चलने वाले आईसीडीएस केंद्रों को 'सीडीआर' के सुपुर्द करने का निर्णया लिया है। 'सीडीआर' एक गैर सरकारी संगठन है जोकि ऐ सेवानिवष्त्त आईएएस आफिसर, मनोहर प्रसाद द्वारा चलाया जा रहा है। आंगनवाड़ी केंद्रों को मावानाती, मावासादा (हमारा गांव – हमारा स्कूल) में रूपांतरित कर दिया जाएगा; आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकष्त बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बाहर से एक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। आईटीडीए ऑफिसर ने स्वयं बताया कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका का कार्य सिमटकर केवल पूरक पोषण उपलब्ध कराना ही रह जाएगा।

आंध्र प्रदेश आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका यूनियन की अदीलाबाद जिला कमेटी ने आंगनवाड़ी केंद्रों से स्कूल पूर्व शिक्षा को हटाने और असल में आईसीडीएस के अस्तित्व को समाप्त करने जैसी कार्यवाहियों के विरूद्ध संघर्ष करने का फैसला लिया। यह संघर्ष कार्यक्रम 28 जून 2008 को कार्यक्रम अधिकारी के ऑफिस के सामने धरने आरम्भ होकर पूरे जिले में फैल गया। 14 जुलाई को हजारों आंगनवाड़ी कर्मचरियों ने कार्यक्रम कलैक्टर की धर पकड़ की। 16–17 जुलाई को बाल विकास परियोजना के ऑफिसरों के ऑफिस के सामने क्रमिक भूख हड़ताल की गई । सरकार को कुछ समय के लिए इस योजना को बांद करना पड़ा।

अदीलाबाद जिले के संघर्ष के जारी रहते हुए भी राज्य सरकार ने मानव विकास संसाधन मंत्रालय के अन्तर्गत समांतर आंगनवाड़ी केंद्र खोलना जारी रखने का निर्णय लिया। परन्तु श्रीकाकुलम जिले में आंगनवाड़ी केंद्र के क्षेत्र में यह कार्यवाही रोकने में कामयाब हो पाई।

हरियाणा में आंगनवाड़ी यूनियन का विरोध प्रदर्शन

सरकार ने पूरक पोषण तैयार करने की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूहों को सौंपी है। स्वयं सहायता समूह, गांव स्तरीय कमेटी, पंचायत सदस्य, सभी दखलअंदाजीं करते हैं और आंगनवाड़ी सेविकाओं को आंगनवाड़ी केंद्र चलाने के लिए इन सब को खुश रखना पड़ता है। सभी 'कुछ' की मांग करते हैं और परिणामस्वरूप नई प्रणाली भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण बन गई है। गरीबों को पूरक पोषण का लाभ नहीं मिल रहा। आंगनवाड़ी सेविका, जोकि इस समूह की संयोजिका है, के नाम पर राशि जमा की जाने वाली राशि केवल इस कीमत पर छोड़ी जाती है कि उस भ्रष्टाचार में शामिल होकर उस राशि को दूसरों के साथ बांटा जाए या स्वयं भ्रष्टाचार का शिकार बनें। सीडीपीओ द्वारा 33 आंगनवाड़ी सेविकाओं को उनकी सेवाओं से निष्कासित कर दिया गया।

यूनियन ने प्रयत्न किया कि इन समस्याओं को विभिन्न प्रकार से प्रशासन के सामने लाया जाए। परन्तु इस समयावधि बीच ही सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों में 'कूपन प्रणाली' आरम्भ करने की घोषणा की। यह कूपन लाभार्थियों को तीन माह के लिए एकसाथ वितरित किए जाऐंगे। यदि बच्चे को पूरक पोषण प्राप्त करना है तो उसे संख्यानुसार यह कूपन लाना होगा। बाद में इन एकत्र हुए कूपनों पर सरपंच को हस्ताक्षर करने होंगें और विभाग द्वारा इसकी जांच की जाएगी! यह प्रणाली 15 अगस्त 2008 से लागू की जानी थी।

सरकार के इस प्रकार के कदमों की घोषणा और सरकार का अपननी बातों से मुकर जाने के बाद यूनियन के पास संघर्ष के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। यूनियन ने निर्णय लिया कि वे 13 और 14 अगस्त को चण्डीगढ़ में आईसीडीएस निदेशक के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे।

उस दिन 13 अगस्त 2008 को भाजपा द्वारा 'बंध' का आहवान् होने पर भी सैंकड़ों आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने भिवानी, जींद, करनाल, हिसार, गुड़गांव, मेवात, फरीदाबाद, औश्र यमुना नगर जिलों से आईसीडभ्एस ऑफिस के समक्ष एकत्र हुईं। वे बहुत ही शांत धरने पर बैठी थीं, जिसे हरियाणा सीआइटीयू महासचिव सुरेंद्र मलिक, हरियाणा एसकेएस अध्यक्ष आज़ाद मलिक, आइफा कोषाध्यक्ष ए आर सिंधु ने संबोधित किया। उन सभी ने जनविरोधी नीतियों और आम आदमी की जिंदगी पर इन नीतियों के पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया। सिंधु ने आईसीडीएस में, विश्व बैंक के निर्देशों पर सरकार द्वारा प्रस्तावित बदलावों के बारे में विस्तार से बताया।

डायरेक्टर और कमिश्नर दोनों ही ऑफिस से नदारद थे। डेप्युटी डायरेक्टर यूनियन से बात करने की इच्छुक थी, परन्तु संघर्षशील आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उनसे बात करने के मूड में बिल्कुल भी नही थे। डायरेक्टर ने यूनियन नेतष्वमंडल

से फोन पर बात की और कहा कि उन्हें यूनियन के रिप्रजेन्टेशन और विरोध के बारे में जानकारी नही थी और 19 अगस्त को यूनियन से मिलने की इच्छा जताई। यूनियन ने कूपन प्रणाली को तुरन्त वापस लेने पर ज़ोर दिया और निष्कासित किए गए कार्यकर्ताओं की पुनः लम्बित जांच करने पर जोर दिया।

इसी बीच मुख्य मंत्री के ओएसडी धरनास्थल पर आए और मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय तय करवाने का आश्वासन दिया। धरना अगले दिन भी ज़ारी रहा और अगले दिन धरने में दो हज़ार से अधिक आंगनवाड़्ऱी कर्मचारियों ने भाग लिया।

19 अगस्त को यूनियन का प्रतिनिधिमंडल डायरेक्टर से मिला, परन्तु वह कूपन प्रणाली को वापस करने पर राजी नही हुई और को कहा गया कि इसे दो – तीन माह तक जारी रखने का प्रयत्न करें, तग इसकी समीक्षा की जा सकती है। यूनियन ने घोषणा की कि किसी भी कीमत पर कूपन प्रणाली लागू नही होगी और उन्होंने सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का आहवान किया कि वे संघर्ष को जारी रखें और 20 अगस्त 2008 की आम हड़ताल में भाग लें और हड़ताल के बाद यूनियन भविष्य के कदम तय करेगी।

हरियाणा : रोहतक में अतिथि अध्यापकों पर पुलिस का बर्बर दमन

पिछले दो वर्षो से अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे राज्य के हजारों अतिथि अध्यापकों पर 7 सितम्बर, 2008 को रोहतक में उस समय पुलिस ने अन्धाधुंध फायरिंग की जब वे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुडा को मिलने के लिए जा रहे थे। बताया जाता है कि हरियाणा राजकीय अध्यापक संघ–70 (सम्बद्ध सर्व कर्मचारी संघ व एसटीएफआइ) की ओर से स्थानीय देवी लाल पार्क में रैली के लिए उपायुक्त को प्रार्थना पत्र दिया था। जिला प्रशासन ने उन्हें प्रार्थना पत्र की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की कोई सूचना नहीं दी। जब अध्यापक वहां रैली करने के लिए पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक खदेड़ दिया और उनका सामान बिखेर दिया।

बाद में प्रशासन के कहने पर अतिथि अध्यापक छोटू राम स्टेडियम में रैली करने पर सहमत हो गए। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार उन्होंने रैली के बाद मुख्यमंत्री जो उस दिन शहर में ही थे, को ज्ञापन देने के लिए प्रदर्शन शुरू किया। इस पर पुलिस तथा प्रशासन ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। जब अध्यापकों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन पर बर्बरता से हमला बोल दिया। बिना चेतावनी दिए अध्यापकों को तितर–बितर करने के लिए रबड़ की गोलियां और स्टेनगन से गोलियां चलानी शुरू कर दीं। इसी गोलीबारी में एक अध्यापिका राज रानी गम्भीर रूप से घायल हो गई जिसकी बाद में अधिक खून बह जाने के कारण मौत हो गई।
उल्लेखनीय है कि इस समय राज्य के अनेक सरकारी स्कूलों में 15 हजार से अधिक शिक्षक अतिथि अध्यापकों के रूप में काम करते हैं। वे पिछले दो सालों से नियमित करने की मांग को लेकर आंदोलन चला रहे हैं किन्तु राज्य सरकार ने सिद्धा'न्त रूप में इस पर अपनी सहमति दिए जाने पर भी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। आगे चल कर उसने अध्यापकों के साथ बातचीत करने से ही इन्कार कर दिया। ये अध्यापक इसी विषय पर बातचीत के लिए मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे।

इसी बीच सीआइटीयू की हरियाणा राज्य समिति ने अतिथि अध्यापकों पर पुलिस की बर्बर फायरिंग की तीखे शब्दों में निंदा की है। उसने पूरी घटना की न्यायिक जांच कराने और मृतक अध यापिका राज रानी के पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। सीआइटीयू ने जनता के सभी तबकों को आह्वान किया है कि वे प्रदेश सरकार की बढ़ती निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रतिरोध संगठित करें।

नाभिकीय डील और बिजली: जनता से धोखाधड़ी

दीपंकर मुखर्जी

नाभिकीय सौदे के लिए एनएसजी की छूट हासिल होने के बाद से, इस मुद्दे पर सरकार ने और मीडिया की प्रचार मशीन ने ऐसा झूठ समा बांधा है कि पूछिए ही मत। देश की 42.2 फीसद आबादी को, जो 2001 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार रौशनी करने तक के लिए बिजली से महरूम है, दिन रात एक ही बात समझाई जा रही है कि बस ज़रा सा इंतज़ार और करें। वाशिंगटन में 1,2,3 पर दस्तखत हुए नही कि हमारे देश में हर घर में बिजली पहुंची नही। सिर्फ राजनैतिक नौसिखिए ही नही है जो देश की शशिक्रलाओं और कलावतियों को यह पाठ पढ़ा रहे हैं बल्कि प्रणव मुखर्जी जैसे मंजे हुए नेता भी, खुद अर्थशास्त्र के विद्वान प्रधानमंत्री भी, चिदंबरम और सिब्बल जैसे वकील भी और ज़ाहिर है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम ढिंढोरची, यही गीत गा रहे हैं। शेक्सपीयर के नाटक के सीजर की तरह बराबर उनकी पुकार सुनाई दे रही है – दोस्तों, हिंदुस्तानियों, देशवासियों! ज़रा सा इंतज़ार और कि बुश के साथ नाभिकीय डील होते ही, बिजली आपके इशारे पर नाचेगी।

जनता से वचनों का क्या हुआ?

क्या यूपीए सरकार और खासतौर पर कांग्रेस के नेतागण स्मर्षतिलोप के शिकार हैं ? या उन्हें लगता है कि देश की जनता इतनी बुद्धू है कि वह चंद साल पहले ही इस सरकार के किए वादे को आसानी से भल जाएगी। आखिरकार 2005 के फरवरी के महीने में राष्ट्रीय बिजली नीति (एन ई पी) में इस सरकार ने जनता से क्या वादा किया था ? ये नीतिगत वचनबद्धताएं तो 2005 के ही जुलाई के महीने में बुश के साथ नाभिकीय डील के संबंध में मनमोहन सिंह द्वारा संयुक्त घोषणा पत्र पर दस्तखत किए जाने के भी पहले की है।

राष्ट्रीय बिजली नीति में सरकार ने निम्नलिखित घोषणाएं की थीं :

☐ बिजली तक पहुंच – हरेक घर को अगले पांच बरस में।

☐ बिजली की उपलब्धता – 2012 तक बिजली की मांग पूरी होने लगेगी; पीक टाइम मांग की कमी को भी दूर किया जाएगा।

☐ बिजली की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता 2012 तक बढ़ाकर 1000 यूनिट प्रति व्यक्ति कर दी जाएगी, जबकि यूपीए के सत्ता संभालने के समय यही उपलब्धता 631 यूनिट प्रतिव्यक्ति ही थी।

ज़ाहिर है कि जनता को दिए गए सरकार के ये वचन किसी भी तरह से भारत अमरीका नाभिकीय डील से नही जुड़े नही हुए थे। आइये, अब एक नज़र भारत सरकार के बिजली मंत्रालय की ताज़ातरीन रिपोर्ट पर डाल लें। 2007–08 की इस रिपोर्ट के चौथे अध्याय में, जिसका शीर्षक है "ग्यारहवीं योजना में (उत्पादन) क्षमता में बढ़ोतरी का कार्यक्रम" पैरा 3 में जो कुछ कहा गया है इस प्रकार है:

" राष्ट्रीय बिजली नीति (एन इ पी) में यह कल्पना रखी गई है कि 2012 तक सबको बिजली मिल जाएगी और बिजली का प्रतिव्यक्ति सालाना उपभोग, 631 यूनिट के मौजूदा स्तर से बढ़कर 1000 यूनिट हो जाएगा। एन इ पी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, ग्यारहवीं योजना में 78,577 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता जोड़े जाने का प्रस्ताव किया गया है। (बिजली उत्पादन) क्षमता में इस बढ़ोतरी से बिजली क्षेत्र को 9.5 फीसद वृद्धि दर हासिल होने की उम्मीद की जाती है। क्षमता में बढ़ोतरी का ब्रेक इस प्रकार (तालिका के अनुसार) रहेगा।

इस तरह न्यूक्लियर डील के साथ वह ना हो तो उसके बिना भी सही, 2012 तक हर घर को बिजली पहुचाने के वचन को पूरा करने के लिए 78,577 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता जोड़नी पड़ेगी और इसमें से सिर्फ 3380 मेगावाट बिजली नाभिकीय स्त्रोत से आनी है। हालांकि हमारे देश में सक्रिय अमरीका परस्त लॉबी इसे ही हमारे देश कीं बिजली की कमी की समस्या रामबाण इलाज बनाकर पेश कर रही है। अब अगर हमारे देश की बुश मित्र सरकार और ऊर्जा निरक्षर मीडिया ने नाभिकीय बिजली उत्पादन में सह सारी की सारी बढ़ोतरी बुश प्रशासन को ही समर्पित करने का फैसला कर लिया है, तो वही सही। बहरहाल, मनमोहन सिंह सरकार को जनता के एक सवाल का जवाब तो देना ही होगा – **पांच साल में बिजली उत्पादन क्षमता में नाभिकीय क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में जो 75,195 मेगावाट का इजाफा होना था, उसका क्या हुआ ?**

क्षेत्र	जल	ताप	नाभिकीय	कुल मेगावाट (फीसद)	
केंद्रिय	9685	26,800	3380	39,865	(50.7)
राज्य	3605	24,347	0	27,952	(35.5)
निजी	3263	7,497	0	10,760	(13.8)
कुल	**16,553 (21 फी0)**	**58,644 (74.4 फी0)**	**3,380(4.4 फी0)**	**78,577**	**(100 फी0)**

2008 तक सरकार कितना इजाफा कर पाई है ?

अब तक कहां पहुंचे ?

पांच साल में 75,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ने के लिए, हर साल 15,000 मेगावाट क्षमता जोड़ने की जरूरत होगी। आखिरकार यूपीए सरकार इस मामले में कितनी दूर तक जा पाई है ? यूपीए ससकार ने जब सत्ता संभाली थी, उस समय देश की बिजली उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता थी — 1,12,000 मेगावाट। इसके 44 महीने बाद, 31 जनवरी 2008 तक यह क्षमता 1,41,000 मेगावाट तक पहुंचाई जा सकी थी यानी इसमें 30,000 मेगावाट से भी क्षमता ही जोड़ी जा सकती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले से घोषित लक्ष्य को हासिल करने के लिए , जल तथा ताप विद्युत की मदों में 15,000 मेगावाट सालाना की जो बढ़ोतरी की जानी थी उसके ऊपर से बची हुई अवधि में हर साल 8,000 मेगावाट का और इजाफा करना होगा यानि जों सालाना लक्ष्य बनता था अब बिजली उत्पादन क्षमता में उससे डेढ़ गुनी बढ़ोतरी करनी होगी। आखिरकार तय लक्ष्य से इस तरह पिछड़ने के लिए जिम्मेदार कौन है ? क्या इसके लिए बिजली क्षमता के कम रहने या नाभिकीय डील ना हो पाने को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है ? ज़ाहिर है कि इस मामले में शशिकला तथा कलावती और दूसरे लोग जार्ज बुश से या एक्प्रैसवालों या टाईम्सवालों या टीवी चैनलों के धन्नासेठ मीडिया से तो सफाई मागे जाने से रहे, वे तो मनमोहन सिंह और उनके न्यूक्लियर वालों से इसका जवाब मांगेंगे कि बिजली के मामले में ऐसा क्यों हुआ ?

बाढ, उत्तरी कनपरा, सिपत व कहलगांव में एनटीपीसी के कोयला आधारित थर्मल़ बिजलीघरों से 3,960 मेगावाट (6 X 660) द्वामता के निर्माण में जो देरी हुई और कवास तथा गंधार में उसके गैस आधारित बिजलीघरों से 2,600 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता की स्थापना में जो देरी हुई, वह क्या किसी ''नाभिकीय अलगाव'' का या ''प्रोद्यौगिकी तक पहुंच के अभाव'' का नतीजा थी ? कांग्रेस समर्थित लैनको (एल ए एन सी ओ) और उसके शत्रु से मित्र बन गए लोगों द्वारा समर्थित रिलायंस एनर्जी लिमिटेड के बीच नैगम झगड़े के चलते रूकी पड़ी 4,000 मेंगावाट की सासन की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के शुरू होने में देरी के लिए कौन जिम्मेदार है ? बाढ के बिजलीघर के उपकरणों की खरीद में हुए दलालीखने के घोटाले के मामले में, जिसके चलते इस अनुचित योजना में विलंब हुआ है, प्रधानमंत्री तथा उनके न्यूक्लियर वाले आखिर क्या कर रहे थे ? क्यों सरकार अपनी ही कंपनी एन टी पी सी की इसमें मदद नही कर पाई कि वह रिलाइंस इंडस्ट्रिज़ लिमिटेड को 2005 के सौदे में तय की गई कीमत पर ही गैस की आपूर्ति देने के लिए मजबूर करे ?

यह धोखाधड़ी माफ नही करेगी जनता

और आखिरी, किंतु महत्व में सबसे आखिरी नही सवाल यह कि न्यूक्लियर डील की ही तरह पूरी तरह से मीडिया द्वारा समर्थित और मनमोहन सिंह – मोंटेक सिंह प्रेरित उस डाभोल / एनरॉन डील का क्या हुआ, जिससे अब से एक दशक पहले ही बिजली की कमी के मारे महाराष्ट्र को 2,140 मेगावाट बिजली मिलनी थी ? याद रहे कि यह बिजलीघर आर्थिक रूप से अवहनीय साबित होने के चलते, 2001 में बंद हो गया था। लेकिन काफी तड़क भड़क के साथ और सार्वजनिक पैसा लगाकर 2005 में यूपीए की सरकार ने इस बिजलीघर को पुर्नजीवित किया क्योंकि देश की ऊर्जा सुरक्षा का तकाजा था। यह दूसरी बात है कि यह परियोजना अब भी अवहनीय की अवहनीय ही बनी हुई है।

एनरॉन डील कराने वालों को वे चाहे कांग्रेसी हों भाजपाई, जनता ने चुनाव में इसलिए सत्ता से निकाल बाहर किया था कि उन्हें घर घर बिजली पहुंचाने के झूठै दिलासे देकर, महाराष्ट्र की जनता की आंखों में धूल झोंकी थी। फिर इस देश की जनता उन न्यूक्लियर डील करने वालों को सत्ता से बाहर करने में क्यों हिचकने लगी जिन्होंने इस तरह के प्रचार के ज़रिए पूरे देश की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है कि बिजली की कमी को दूर करने के लिए नाभिकीय डील ज़रूरी है।

उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी कर्मचारियों का पहला राज्य सम्मेलन

उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का पहला राज्य सम्मेलन 28–29 सितम्बर, 2008 को ब्रास सिटी मोरादाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। सम्मेलन स्थल का नाम स्वतंत्रता सेनानी और ट्रेड यूनियन आंदोलन के नेता हरकिशन सिंह सुरजीत के नाम पर रखा गया था।

सम्मेलन के आरम्भ में आइफा महासचिव हेमलता ने सीआइटीयू का ध्वज फहराया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। खुले सत्र की अध्यक्षता यूनियन के संस्थापक सदस्य बिंदुबाला सिंह ने की। स्वागत समिति के अध्यक्ष डा0 स्वर्ण नागिया ने सम्मेलन में राज्यभर से आई 600 आंगनवाड़ी कर्मचारियों का स्वागत किया। चंद्र पाल आज़ाद ने सत्र का संचालन किया।

कई जिलों में आंगनवाड़ी कर्मचारियों को संगठित करने और सम्मेलन आयोजित करने के लिए फैडरेशन की महासचिव हेमलता ने आयोजक कमेटी को बधाई दी। उन्होंने विश्व बैंक की सहायता से चलने वाले आईसीडीएस 'रिफार्मस्' परियोजना 4 के घातक परिणामों के बारे में बताया जोकि उत्तर प्रदेश के साथ सात अन्य राज्यों में कियान्वित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन बदलावों से तो आईसीडीएस को अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, ओर इससे नेतृत्व होगा आईसीडीएस के निजीकरण और समाप्ति का। उन्होंने जोर दिया कि इन बदलावों के विरोध में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जाए और लाभार्थियों को भी इस आंदोलन में शामिल किया जाए।

उत्तर प्रदेश सीआइटीयू राज्य कमेटी के महासचिव दौलत राम ने सरकार की जन विरोधी नीतियों की आलोचना की और आंगनवाड़ी कर्मचारियों को राज्यभर में युनियन को मजबूत बनाने का आहवान किया। स्कूल टीचर्स फैडरेशन ऑफ इंडिया , डीवाईएफआई, एआइकेएस, एफएमआरएआई इत्यादी जैसे बहुत से भ्रातृ संगठनों के राज्य स्तरीय नेताओं ने सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को बधाई दी और समर्थन जताया।

प्रतिनिधि सत्र सांय आरम्भ हुआ जिसमें 16 जिलों से 262 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बिंदुबाला सिंह, करूणा चौधरी, अवध राज, सरोज वर्मा, चमन आरा, कुसुम गिरी और अखिलेश राघव सहित अध्यक्षमंडल ने प्रतिनिधि सत्र की कार्यवाही का संचालन किया। फैडरेशन की महासचिव हेमलता ने सम्मेलन का उद्घाटन किया।

आयोजक कमेटी की संयोजिका वीना गुप्ता ने रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें राज्यभर की आंगनवाड़ी कर्मचारियों की स्थिति और आयोजक कमेटी के गठन के बाद की गतिविधियों का विस्तार से वर्णन किया गया था। सभी जिलों से 29 प्रतिनिधियों ने बहस में भाग लिया और अपनी अपनी समस्याओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जो लाभ उन्हें मिलने चाहिए वे उन्हें नही मिल रहे हैं। प्रस्तुत मांगों पर उन्होंने यूनियन से जुड़े रहने इच्छा जताई। वीना गुप्ता द्वारा बहस के जवाब देने के बाद रिपोर्ट को सर्वसम्मति से स्वीकारा गया।

सम्मेलन में एक मांगपत्र स्वीकारा गया और 28 नवम्बर को लखनऊ में एक विशाल रैली आयोजित करने का निर्णय लिया गया। सम्मेलन के आरम्भ से अंत तक दौलत राम उपस्थित रहे और दिशा निर्देश देते रहे।

सम्मेलन में सर्वसम्मति से 45 सदस्यों की एक्ज़ीक्यूटिव कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी नरेंद्र शर्मा को अध्यक्ष, करूणा चौधरी को कार्यकारी अध्यक्ष और , वीना गुप्ता को महासचिव, संध्या पवार को कोषाध्यक्ष और चमन आरा को सहायक कोषाध्यक्ष के रूप में स्वीकारा गया।

चंद्रपाल आज़ाद ने सम्मेलन को सफल बनाने और समर्थन देने वालों, सभी का धन्यवाद अदा किया।

(पृष्ठ 5 का शेष)

सी मुसीबतों को मजदूर झेलते हुए भी संघर्षों में भाग ले रहे हैं। महिला मजदूरों को घर और बाहर देनों ही ओर की मुसीबतों से जूझना पड़ता है परन्तु वे भी पुरूष मजदूरों के कदम से कदम मिलाकर संघर्षों में भाग ले रही हैं। ये मजदूर संघर्ष के रास्ते पर विश्वास करते हैं।

एक रिवाल्यूशनरी टेड यूनियन होने के नाते सीआईटीयू को मजदूर वर्ग की एकता को मजबूत करने और इनकी चेतना को बढ़ाने का उत्तरदायित्व उठाना होगा।

अपने बहुत से सम्मेलनों में सीआईटीयू सामाजिक मुद्दों को उठाने पर जोर दिया है जैसे दलितों की समस्याएं, महिलाओं के मुद्दे इत्यादी और सांप्रदायिक ताकतों की विभाजन की नीतियों का कड़ा विरोध किया है। बड़ी संख्या में महिलाए, आंगनवाड़ी कर्मचारी , मिड डे मील मजदूर, ग्रामीण स्वास्थ्य मजदूर म्यूनिसिपल मजदूर इत्यादी सीआईटीयू के संघर्ष कार्यकमों में सकिय होकर भाग ले रहे हैं। इनका विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और सीआइटीयू की यूनियनों में इन्हें और अधिक उत्तरदायित्व सौंपा जा रहा है।

सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सीआईटीयू को मजबूत करना और इसे एक अखिल भारतीय संगठन में विकास करना जिससे एकता मजबूत करने के काम को स्वरूप दिया जा सके और साम्राज्यवादी भूमंडलीयकरण को पराजित करने के संघर्ष को तेज किया जा सके।

कामरेड हरकिशन सिंह सुरजीत

प्रख्यात क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और किसान आंदोलन के अग्र गण्य नेता कामरेड हरकिशन सिंह सुरजीत नहीं रहे। देश में कम्युनिस्ट आंदोलन के इस असाधारण नेता का गत 1 अगस्त, 2008 को लम्बी बीमारी के बाद नौएडा के मैट्रो अस्पताल में देहांत हो गया। कामरेड सुरजीत ने शहीदे आजम सरदार भगत सिंह की शहादत से प्रेरणा लेकर मात्र सोलह वर्ष की आयु में अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरूआत की थी। उन्होंने उस समय अर्थात् 1932 में होशियारपुर की जिला कचहरियों पर लगे ब्रिटेन के यूनियन जैक को उतार कर तिरंगा झण्डा फहराया था। उन्हें गिरफ्तार करके बाल सुधार गृह में भेज दिया गया।

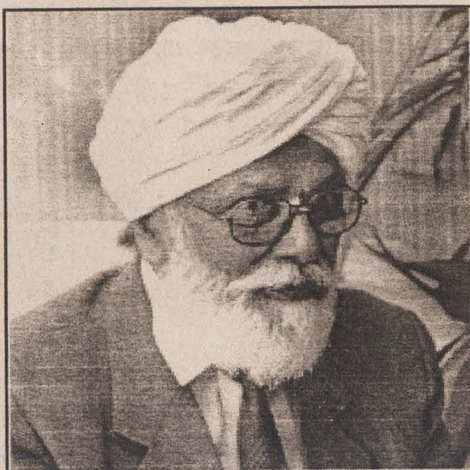

कामरेड सुरजीत वर्ष 1934 में कम्युनिस्ट आंदोलन में शामिल हुए और उसके अगले ही वर्ष 1935 में वह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। उन्हें 1936 में पंजाब किसान सभा का सचिव चुना गया। उसके दो साल बाद उन्हें उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते पंजाब से देश निकाला दे दिया गया और वह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर में आकर काम करने लगे। यह पर उन्होंने एक मासिक पत्र 'चिंगारी' निकाला। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाने के बाद उन्हें भूमिगत हो जाना पड़ा और वर्ष 1940 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें लाहौर के लाल किले में कैद रखा गया जो उन दिनों देशभक्तों को अमानवीय यातनाएं दिए जाने के मामले में बदनाम था। तीन महीनों तक वह अत्यंत भयावह स्थितियों में काल कोठरी में बंद रहे। उसके बाद उन्हें देवली नजरबंदी शिविर में भेज दिया गया जहां वह 1944 तक रहे।

देश के विभाजन के समय उन्होंने साम्प्रदायिक सदभावना बनाए रखने के लिए अथक परिश्रम किया जबकि उन दिनों पूरा पंजाब साम्प्रदायिक हिंसा की आग में बुरी तरह जल रहा था। यह उन्हीं के कठोर परिश्रम और सजगता का परिणाम था कि साम्प्रदायिकता की भयानक आंधी में भी उनका गांव बुंडाला (जिला जालन्धर) एक अपवाद बना जहां उन्होंने अपने दूसरे संगी–साथियों के साथ मिल कर एक भी मुसलमान की हत्या नहीं होने दी और धार्मिक उन्मादियों का पूरे साहस के साथ मुकाबला किया। उन्होंने अपने जीवन के दस वर्ष जेल में बिताए थे जिनमें से आठ वर्ष का समय ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की जेलों में बिताया गया था। वह आठ वर्ष तक भूमिगत भी रहे थे।

कामरेड सुरजीत का किसान आंदोलन से पुराना नाता था। उन्होंने पंजाब में वर्ष 1959 में बैटरमैंट लेवी के खिलाफ चले किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्होंने लम्बे समय तक अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा महासचिव के रूप में काम किया था। उन्हें वर्श 1950 में पंजाब कम्युनिस्ट पार्टी का सचिव चुना गया। वह 1954 में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की तीसरी कांग्रेस में केन्द्रीय समिति तथा पोलित ब्यूरो के सदस्य चुने गए। कामरेड सुरजीत देश के उन प्रमुख कम्युनिस्ट नेताओं में से एक थे जिन्होंने संशोधनवाद के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया था और आगे चल कर 1964 में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का गठन किया। वह इस नव गठित पार्टी की पोलित ब्यूरो के सदस्य चुने गए। उन्हें 1992 में पार्टी का महासचिव चुना गया। वह इस पद पर 2005 तक रहे जब उन्होंने अपनी खराब सेहत के चलते पद से मुक्त होने की इच्छा व्यक्त की थी।

कामरेड सुरजीत देश के उन चन्द नेताओं में से एक थे जिन्होंने साम्प्रदायिकता के खतरे को भांपा था और साम्प्रदायिक ताकतों के उभार के खिलाफ और भारत के धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्तों के लिए अग्रिम पंक्तियों में शामिल होकर संघर्ष किया था। उन्होंने 1989, 1996 तथा 2004 में राजनैतिक गठबंधनों के गठन में निर्णायक भूमिका निभाई थी। उन्होंने विभाजक एवं अलगाववादी ताकतों के खतरे के खिलाफ न केवल जोरदार संघर्ष चलाया बल्कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के काम में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। उन्होंने खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ संघर्ष में दृढ़ रुख अपनाया था।

कामरेड सुरजीत ने देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन में भी गहरी दिलचस्पी ली और उन्होंने सदा जन आंदोलनों में मजदूर–किसान एकता के लिए काम किया और हमेशा इस बात पर जोर दिया था कि किसानों को शोषण एवं दमन के खिलाफ ट्रेड यूनियन संघर्ष का समर्थन करना चाहिए। सीआइटीयू वर्ष 2002 का स्मरण करता है जब वह बी टी रणदिवे भवन में आए थे। उन्होंने सीआइटीयू केन्द्र के कार्यों में गहरी दिलचस्पी ली थी और कार्यालय मे काम करने वाले प्रत्येक साथी से वह बड़े स्नेह से मिले थे। सीआइटीयू देश के इस महान क्रांतिकारी नेता को पूरे आदर के साथ श्रद्धांजलि भेंट करता है और उनके परिवार के शोकाकुल सदस्यों तथा असंख्य सहयोगियों एवं प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता है।

आईसीडीएस पर संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन

सीआइटीयू, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेतिहर मजदूर यूनियन और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन 22 अक्टूबर 2008 को मावलंकर हॉल, नई दिल्ली में एक संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन आयोजित करेंगे। इस कन्वेंशन में देशभर से आंगनवाड़ी कर्मचारी, मजदूर, किसानए खेतिहर मजदूर और महिलाएं भाग लेंगी।

सरकार ने देशभर में 2008–09 के 'ए रिवाइज़्ड नैशलन इंपलीमेंटेशन फ्रेमवर्क' को परिचित कराने और समन्वित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) का पुर्नगठन करने का फेसला लिया है। विश्व बैंक की सहायता से चलाए जाने वाले आईसीडीएस रिफॉर्म प्रोजैक्ट – 4 इस 'रिवाइज़्ड इंपलीमेंटेशन फ्रेमवर्क' को शुरूअती तौर पर आरम्भ करने के लिए बहुत ही उत्सुक है।

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन लंबे समय से लगातार आईसीडीएस बचाओ अभियान चला रही है। सीआईटीयू ने भी ये मुद्दे प्रधानमंत्री के समक्ष उठाए। परन्तु सरकार कभी फेसले लेने में असली 'भागीदारों' आंगनवाड़ी कर्मचारियों या लाभार्थी संगठनों जैसे महिला संगठन, किसान या खेतिहर मजदूरों के संगठनों से सलाह मशविरा नही करती।

आईसीडीएस के पुर्नगठन का मुद्दा बच्चों के पोषण स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकार से जुड़ा हुआ है इसलिए अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन और सीआइटीयू ने अन्य संगठनों के साथ मिलकर यह मुद्दा उठाने का फैसला लिया है।

सीआइटीयू, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेतिहर मजदूर यूनियन और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, और आइफा के नेताओं की एक बैठक 29 अगस्त 2008 को बीटीआर भवन, नई दिल्ली में हुई। बैठक में सीआइटीयू अध्यक्ष एम के पंधे एवं सीआइटीयू सचिव तपन सेन, अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव के वरद राजन, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के सचिव सुनीत चोपड़ा, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की महासचिव सुधा सुंदररमन, सीआइटीयू सचिव एवं आइफा महासचिव के हेमलता एवं आठफा कोषाध्यक्ष ए आर सिंधु ने भाग लिया।

बैठक में आईसीडीएस के पुर्नगठन और नियमितिकरण के मुद्दे पर संयुक्त अभियान और प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक के निर्णयों के अनुसार आईसीडीएस के लाभार्थियों का प्रतिनिधित्व कर रहे संगठनों सीआइटीयू, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेतिहर मजदूर यूनियन और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखे कि आईसीडीएस में कोई बदलाव लाने से पूर्व सभी स्टेक होल्डर्स से मशविरा किया जाए।

22 अक्टूबर 2008 को होने वाली अखिल भारतीय कन्वेंशन घोषणा पत्र को अंतिम रूप देगी और निम्न मांगों पर भविष्य के कदम सुनिश्चित किया जाएगा।

६ बच्चों और महिलाओं के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित किया जाए

६ आईसीडीएस का सर्वव्यापीकरण और इंस्टीटयूशनलाइजेशन किया जाए

६ विश्व बैंक द्वारा निदेशित आईसीडीएस का पुर्नगठन नही किया जाए।

६ आंगनवाड़ी सेविकाओं को ग्रेड 3 व सहायिकाओं को ग्रेड 4 के कर्मचारियों के रूप में नियमित किया जाए; इनकी कामकाजी स्थिति में सुधार लाया जाए।

के हेमलता द्वारा, अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति (सीटू) के लिए, ए–13, राउस ऐवेन्यू, नई दिल्ली से संपादित एवं प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए–21, झिलमिल इंडस्टीयल एरिया, जी टी रोड, शाहदरा दिल्ली–95 से मुद्रित